Scheme where the Government of India is ready to support State Government, and the State Government to take certain responsibility of procurement and the responsibility of sharing losses; 50 per cent losses will be borne by the Government of India and 50 per cent will be borne by the respective Government. If Bihar or any other Government, whether it is for onion or whether it is for potato, they are ready to communicate to the Government of India to introduce this Scheme in that particular State, the Government of India will willingly protect the interests of the farmers from distress sale. And whatever we purchase, we will try to export also.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप: सभापति महोदय, प्याज के दाम बढ़ने की कई वजह हैं, इसका बढ़ता हुआ निर्यात भी है, बिचौलियापन भी है। मैं यह समझता हूं कि सबसे ज्यादा प्याज के दाम बढ़ने की वजह कम उत्पादन और अधिक मांग है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को कुछ आर्थिक सहयोग देकर, उनको प्रोत्साहित करने की योजना सरकार रखती है ताकि प्याज का उत्पादन बढ़े और महंगाई कम हो सके?

श्री शरद पवार: सर, मुझे खुशी है कि आज देश में प्याज का उत्पादन बहुत बढ़ा है। किसानों की शिकायत यह है कि उनको मार्केट में ठीक तरह से कीमत नहीं मिलती है। उत्पादन बढ़ा है, कीमतें बहुत नीचे आयी हैं और इस बारें में एक प्रकार की नाराजगी भी किसानों में है। ऐसी परिस्थिति में रास्ता एक ही है - यहां तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ नहीं होता है - ऐसी स्थिति में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का लाभ लेना ही एक रास्ता है और हमने यह कहा है कि सरकार इसके लिए तैयार है।

MR. CHAIRMAN: Q.No. 364 - Hon'ble Member absent.

*364. *[The questioner Shri Pyarimohan Mohapatra was absent]

Investment in Coal India Ltd. and Mahanadi Coalfields Ltd.

*364. SHRIPYARIMOHAN MOHAPATRA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the Rate of Return (RoR) on investment in Coal India Ltd. and Mahanadi Coalfields Ltd.; and

(b) the proportional change in RoR due to unit increase in percentage of royalty?

THE MINISTER OF COAL (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (b) A statement is laid on the Table of House.

Statement

(a) As per the Ministry of Finance, Government of India directives vide 1(5)/PF.II/2001 dated 15.11.2007, all the coal mine projects of CIL and MCL are having the rate of return @ 12% or more.

(b) There is no co-relation between increase of royalty rates on coal and the RoR on investment in CIL as the royalty is collected from the coal consumers by the concerned subsidiary of CIL and paid to the concerned State Government.

MR. CHAIRMAN: मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रतीत होता है कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस पर वे 12 प्रतिशत रिटर्न कमा रहे हैं। यह तो अच्छा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ, देश में कोयले के लिए परेशानी होती है क्योंकि बिजली के लिए कोयले की जरूरत है और 64 परसेंट बिजली का उत्पादन कोयले पर निर्भर है। माननीय प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति का लाभ लेते हुए, मेरा एक सवाल है कि इन आवश्यकताओं को देखते हुए एक बिल है जो स्टैंडिंग कमेटी से एप्रूव्ड है और इस हाउस में पेंडिंग है जिसके अंतर्गत आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी पारदर्शी प्रमाणिक तरीके से कमर्शियल एक्सप्लायटेशन के लिए अवसर देंगे। क्या आपकी सरकार का ऐसा मत है कि बिजली के लिए कोयले की कमी को देखते हुए, रिफार्म्स के अंतर्गत इस दिशा में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं की ज्यादातर आपूर्ति कोयले से ही होती है। कोयले का उत्पादन बढ़ाने से हमारे देश की ऊर्जा का उत्पादन बढ़ सकता है। इसके लिए निरंतर प्रयत्न किए जाते रहे हैं। बहुत सारे कोल ब्लॉक्स भी दिए गए हैं, जबकि कोल ब्लॉक्स के माध्यम से यह उम्मीद की गई थी कि उनसे कोयले का उत्पादन बढ़ेगा और हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति होगी। लेकिन जितने कोयले के उत्पादन की कल्पना की गई थी, उतने कोयले का उत्पादन नही बढ़ पाया। उसके बहुत से कारण हैं, जैसे लैंड इक्विज़िशन की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारे व्यवधानों की वजह से उतने कोयले का उत्पादन नहीं हो पाता, जितना कि हमारे देश की आवश्यकता है।

वैसे हमारे देश की आवश्यकताएं भी पिछले पांच-सात सालों से तेजी से बढ़ी हैं। देश में जिस तेजी के साथ industrialization हुआ है और जिस तेजी से ऊर्जा की मांग बढ़ी है, उनके अनुरूप कोयले का उत्पादन नहीं हो पाया है। इसके लिए सलाह दी गई है कि जो लोग कोयले की आवश्यकता महसूस करते हैं, जो लोग पावर प्लांट लगा रहे हैं, उनको थोड़ा विदेशों की ओर भी झांकना चाहिए और वहां से कोयला आयात करना चाहिए, ताकि हमारे देश की कोयले की मांग को पूरा किया जा सके।

माननीय सदस्य ने जिस बिल के बारे में कहा है, वह बिल आज भी राज्य सभा में लम्बित है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कोई ऐसा consensus develop होगा, जिसमें सभी लोग मिलकर देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: मंत्री जी, वह सात सालों से पैंडिंग हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हां, इसमें कोई शक नहीं है कि वह सात सालों से पेंडिंग है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: क्या आप इसके लिए कोई प्रयास करेंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आपको भी प्रयास करना है और हमें भी प्रयास करना है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: मंत्री तो आप हैं। वह बिल पिछले सात सालों से पैंडिंग है। ...**(व्यवधान)**...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जब सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि कमर्शियल मॉइनिंग का बिल आने वाले समय में पारित हो सकता है और देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं की आपूर्ति की जा सकती है।

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, according to the reply of the Minister, there is no correlation between royalty rates on coal and the RoR on the investment in CIL. It is a fact, Sir. But, it is also a fact that the rate of return is reflected in the price collected from the consumers. My specific question is, if the rate of return increases, will it automatically increase the royalty to the States or not? This is my specific question.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही price बढ़ती है, उसी हिसाब से royalty बढ़ती चली जाती है। हां, यह बात जरूर है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जहां F और G grade का कोयला उत्पादित होता है, उन स्टेट्स में royalty उतनी नहीं बढ़ पाती है। जहां पर improved quality का कोयला मिलता है, वहां पर royalty बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि price बढ़ने के साथ-साथ royalty भी बढ़ती जाती है।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 12 per cent या 12 per cent से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है। यह संतोष की बात हो सकती है, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कोयले की cost of production कितनी बढ़ी हैं और उसके मुकाबले आपने sellign price को इन तीन सालों कि कितना बकाया है? इन दोनों के comparison के बाद जो आपका 12 per cent रिटर्न है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, रिटर्न से संतुष्ट तो कभी नहीं हुआ जा सकता, लेकिन 12 per cent का रिटर्न भी कोई कम नहीं होता है। तीन सालों में कोयले के price एक बार बढ़ाए गए हैं और अभी कोयले के price

बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसका सीधा असर ऊर्जा पर पड़ता है। अगर कोयले के price बढ़ाए जाते हैं तो बिजली की कीमत बढ़ जाती है, जिससे पूरे देश में महंगाई के आसार बढ़ जाते हैं, इसलिए अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

Pending cases

*365. DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the number of cases pending in the Supreme Court and High Courts as on 1 January, 2009, 2010 and 2011 till date, State-wise and Court wise;

(b) the number of cases which are pending for the last 25 years;

(c) the reasons for large number of pending cases;

(d) whether Government proposes to have a time-bound programme for delivering speedy justice; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the information received from the Registry of the Supreme Court, 56,383 matters (32,080 Admission matters and 24,303 Regular matters) were pending in the Supreme Court as on 31.10.2011. Of these, 20,334 matters are less than one year old and are, thus, not in arrears. The balance 36,049 are arrears. The number of cases pending in the High Courts were 42,17,903 as on 30.9.2010.

As on	Cases pending in the Supreme Court	Cases pending in the High Courts
1.1.2009	49819	38,74,090
1.1.2010	55791	40,60,709
1.1.2011	54562	Not available

Details indicating the High Court-wise pendency of both civil and criminal cases, as on 1.1.2009, 1.1.2010 and 30.9.2010 are given in the Statement *(See* below).